



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 13 मई, 1981/23 वैशाख, 1903

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT
NOTIFICATIONS

Simla-2, the 12th May, 1981

LLR-D(6)23/80.—The Punjab Security of State (Himachal Pradesh) (Amendment) Bill, 1980 (Bill No. 11 of 1980) after having received assent of the Governor, Himachal Pradesh on the 11th May, 1981 under Article 200 of the Constitution of India is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as Act No. 11 of 1981.

JAI CHAND MALHOTRA,
Secretary (Law).

Act No. 11 of 1981.

**THE PUNJAB SECURITY OF STATE
(HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 1980**

AN

ACT

to amend the Punjab Security of State Act, 1953 (XII of 1953) as in force in the territories added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 and as made applicable to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the first November, 1966 vide the Government of India Notification No. 4/6/60/-Judl-II-UTL-10, dated 19-1-1960.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

**Short title
and com-
mencement.**

1. (a) This Act may be called the Punjab Security of State (Himachal Pradesh Amendment) Act, 1980.

(b) It shall come into force at once.

**Insertion of
section 4-A.**

2. After the existing section 4 of the Punjab Security of State Act, 1953, as in force in the territories added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 and as made applicable to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966, vide the Government of India Notification No. 4/6/60/Jud-II-UTL-10, dated 19-1-1960, the following new section 4-A along with its heading shall be inserted, namely:—

12 of 1953

31 of 1966

“4-A. Control of camps, drills or parades.—(1) The State Government may in the interest of public prohibit or impose such condition as may be necessary on the holding of camps for performance of drill, parade or taking out processions etc., with or without arms or any article, weapons or implements capable of being used as arms by any class of persons or organisations whose activities are in the opinion of the State Government subversive of law and order.

(2) Any contravention of an order made under this section shall be punishable with imprisonment which may extend to two years, or with fine, or with both.”

Simla-1, the 12th May, 1981

No. LLR-D(6)4/81.—The Himachal Pradesh Extension of Laws and Repealing Bill, 1981 (Bill No. 3 of 1981) after having received assent of the Governor, Himachal Pradesh on the 11th May, 1981 under Article 200 of the Constitution of India is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as Act No. 10 of 1981.

JAI CHAND MALHOTRA,
Secretary (Law).

हिमाचल प्रदेश विधि विस्तारण तथा निरसन अधिनियम, 1981

हिमाचल प्रदेश में प्रथम नवम्बर, 1966 से शीघ्र पूर्व समाविष्ट क्षेत्रों में प्रयोज्य अथवा प्रवृत्त कतिपय विधियों का पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में परिवर्धित क्षेत्रों पर विस्तारण के लिए उपबन्ध करने तथा कतिपय अधिनियमियों की हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रयुक्ति का निरसन करने हेतु

अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो, —

1. (1) यह अधिनियम हिमाचल प्रदेश विधि विस्तारण तथा निरसन अधिनियम, 1981 कहलायेगा ।

संक्षिप्त नाम
तथा प्रारम्भ

(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगा ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरुद्ध न हो, —

परिभाषाएं

- (क) “शासकीय राजपत्र” से अभिप्रेत है—राजपत्र हिमाचल प्रदेश;
- (ख) “पुराने क्षेत्रों” से अभिप्रेत है—प्रथम नवम्बर, 1966 से तत्काल पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्र;
- (ग) “अनुसूची” से अभिप्रेत है—इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (घ) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, हिमाचल प्रदेश सरकार; तथा
- (ङ) “अन्तरित राज्य क्षेत्रों” से अभिप्रेत है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जो राज्य क्षेत्र परिवर्धित किए गए थे ।

3. अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट, समय समय पर यथासंशोधित, अधिनियमिति जो पुराने क्षेत्रों को प्रयोज्य है अथवा उसमें प्रवृत्त है तथा तदधीन बनाये गये सब नियम, विनियमन, अधिसूचनाएं, आदेश तथा उपविधियां तथा जारी किए गए सब निदेश अथवा अनुदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से तुरन्त पूर्व प्रवृत्त हैं एतद्वारा अन्तरित राज्य क्षेत्रों में विस्तारित किए जाते हैं तथा उसमें प्रवृत्त होंगे ।

कतिपय
विधियों का
अन्तरित
क्षेत्रों में
विस्तारण ।

4. धारा 3 में यथानिर्दिष्ट अधिनियमिति अथवा तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उपविधियों अथवा जारी किये गये निदेशों अथवा अनुदेशों में कोई निर्देश;—

कतिपय
निर्देशों का
अर्थान्वयन ।

- (1) किसी विधि जो अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त नहीं है, से ऐसे राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में समरूपी विधि, यदि कोई ऐसे राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है, के लिए निर्देश से अर्थ लगाया जाए; तथा
- (2) हिमाचल प्रदेश राज्य से, चाहे शब्दों के किसी भी रूप में हों, अन्तरित राज्य क्षेत्रों के लिए अन्तर्भूत निर्देश से अर्थ लगाया जाएगा ।

निरसन
तथा व्यावृत्ति।

5. यदि, इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व, अन्तरित राज्य क्षेत्रों में उस अधिनियमित अथवा तदधीन बनाये गये किन्हीं नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं, आदेशों तथा उपविधियों तथा जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों, जिनका उन राज्य क्षेत्रों पर धारा 3 द्वारा विस्तारण किया गया है, के समरूपी कोई विधि प्रवृत्त है, तो अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों सहित वह विधि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाये निरसित मानी जाएगी :

परन्तु ऐसा निरसन,—

- (क) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन अथवा तदधीन सम्यक रूप से की गई अथवा सहन की गई कोई बात ;
- (ख) इस प्रकार निरसित किसी भी विधि के अधीन अर्जित, प्रोदभूत अथवा उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता अथवा दायित्व ;
- (ग) इस प्रकार निरसित ऐसी किसी विधि के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, सम्पहरण या दण्ड पर ; अथवा
- (घ) पूर्वोक्त जैसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, आभार, उत्तरदायित्व, शास्ति, सम्पहरण या दण्ड के सम्बन्ध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर ;

प्रभाव नहीं डालेगा, और ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, उपचार वैसे ही संस्थित किया जा सकेगा, और शास्ति, सम्पहरण या दण्ड वैसे ही अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था :

परन्तु यह और कि इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन की गई कोई बात अथवा कोई कार्यवाही अन्तरित राज्य क्षेत्रों में धारा 3 द्वारा विस्तारित अधिनियमित के समरूपी उपबन्धों के अधीन की गई मानी जाएगी तथा तदनुसार प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस प्रकार विस्तारित अधिनियमित के अधीन की गई किसी बात अथवा किसी कार्यवाही द्वारा अधिक्रान्त नहीं की जाती है।

अनुसूची-I
में विनिर्दिष्ट
अधिनिय-
मित अथवा
नियमों,
इत्यादि की
प्रयोज्यता
को सुविधा-
जनक बनाने
के उद्देश्यों
के लिए
न्यायालयों
अथवा अन्य
अधिकारियों
की शक्तियां

6. अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमित अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, आदेश, उपविधि, निर्देश अथवा अनुदेश, जो धारा 3 में निर्दिष्ट है, की अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रयोज्यता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य के लिए कोई न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी तत्त्वार्थ को प्रभावित किए बिना उसका ऐसे परिवर्तनों सहित जो इसे न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी के समक्ष विषय में ग्रहण करने के लिए आवश्यक या उचित हो, अर्थ लगा सकता है।

7. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य सरकार अथवा किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी की अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के अधीन प्रयोक्तव्य, बनाये गये नियमों, विनियमनों, अधिसूचनाओं तथा उपविधियों और जारी किए गए निदेशों अथवा अनुदेशों जो धारा 3 द्वारा अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में विस्तारित किए गए हैं, में परिवर्धन करने, संशोधन करने, परिवर्तित करने अथवा विखण्डित करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

नियम बनाने की शक्ति का अप्रभावित रहना।

8. यदि अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट अधिनियमिति के उपबन्धों को अन्तर्गत राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है अथवा ऐसे निदेश दे सकती है जो उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

अनुसूची - I

(धारा 3 देखें)

क्र० सं०	वर्ष	अधिनियम की संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1953	7	दा हिमाचल प्रदेश कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट, 1953.

अनुसूची-II

(धारा 6 देखें)

क्रम सं०	वर्ष	अधिनियम की संख्या	अधिनियम का नाम
1	2	3	4
1.	1825	11	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा बंगाल अल्युवियन एण्ड डिल्युवियन रैगुलेशन, 1825.
2.	1920	1	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब लिमिटेशन (कस्टम) ऐक्ट, 1920.
3.	1920	1	भूतपूर्व बिलासपुर रियासत में यथा प्रवृत्त दा पंजाब लिमिटेशन (कस्टम) ऐक्ट, 1920.
4.	1931	2	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब म्युनिसिपल (एक्जेक्यूटिव ओफिसर्ज) ऐक्ट, 1931.
5.	1938	9	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब डेटअर्ज प्रोटेक्शन (अमैण्डमेंट) ऐक्ट, 1938.
6.	1941	5	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब जागीरज ऐक्ट, 1941.
7.	1941	14	दा ईस्ट पंजाब इलैक्ट्रीसिटी (अमरजैसी पावर्ज) ऐक्ट, 1941 जैसा कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है।
8.	1948	11	दा पंजाब मोलैसीज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1948 जैसा कि अन्तरित राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त है।
9.	1948	11	दा पंजाब मोलैसीज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1948 जो भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना संख्या ए० यू० 4/7-61-जुड-II, दिनांक 16 जून, 1962 द्वारा पुराने क्षेत्रों पर विस्तारित किया गया है।

1	2	3	4
10.	1949	30	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा ईस्ट पंजाब ड्रिज कंट्रोल ऐक्ट, 1949।
11.	2008 वि० सं०	1	भूतपूर्व पैम्सू रियासत के पहले समाविष्ट क्षेत्रों में जो अब दा पंजाब रीआरगेनाईजेशन ऐक्ट, 1966 की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़ दिए गए हैं प्रवृत्त दा पैम्सू कोर्ट आफ वार्डज ऐक्ट, 2008 वि० सं०।
12.	1956	38	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब सपैशल पावरज (प्रैस) ऐक्ट, 1956।
13.	1957	18	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब कोर्ट आफ वार्डज (वैलीडेशन आफ एक्सरसाइज आफ पावरज) ऐक्ट, 1957।
14.	1960	39	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब प्राइमरी एजुकेशन ऐक्ट, 1960।
15.	1963	38	अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दा पंजाब स्टेट फैकल्टी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी सिस्टम आफ मैडीसिन ऐक्ट, 1963।

[Authorised English text of the Himachal Pradesh Vidhi Vistarana Tatha Nirsan Vidheyak, 1981, as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

Act No. 10 of 1981.

THE HIMACHAL PRADESH EXTENSION OF LAWS AND REPEALING ACT, 1981

AN

ACT

to provide for the extension of certain laws as applicable to, or in force in, the areas as comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966, to areas as added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 and the repeal of certain enactments in their application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title
and com-
mencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Extension of Laws and Repealing Act, 1981.

(2) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

- (a) 'Official Gazette' means the Rajpatra, Himachal Pradesh;
- (b) 'old areas' means the areas as comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st November, 1966;
- (c) 'Schedule' means a schedule appended to this Act;
- (d) 'State Government' means the Government of Himachal Pradesh; and
- (e) 'transferred territories' means the territories which were added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

Extension of
certain laws
to transfer-
red territor-
ies.

3. The enactment, as amended from time to time, specified in Schedule I, which is applicable to, or is in force in, the old areas and all rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and all directions or instructions issued, thereunder, which are in force immediately before the commencement of this Act, are hereby extended to, and shall be in force in, the transferred territories.

Construc-
tion of cer-
tain referen-
ces.

4. In the enactment, or rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions, or instructions issued, thereunder, as referred to in section 3, any reference—

- (1) to the law which are not in force in the transferred territories shall, in relation to such territories, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in such territories; and
- (2) to the State of Himachal Pradesh, by whatever form of words, shall be construed as including a reference to the transferred territories.

5. If, immediately before the commencement of this Act, there is in force in the transferred territories any law corresponding to the enactment or any of the rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions or instructions issued, thereunder, extended to those territories by section 3 that law including the enactments specified in Schedule II, shall, on the commencement of this Act, save as otherwise expressly provided in this Act, stand repealed:

Repeal and savings.

Provided that such repeal shall not affect,—

- (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder, or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed, or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed, or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment, as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed:

Provided further that anything done or any action taken under any law so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the enactment extended by section 3 to the transferred territories and shall continue to be in force accordingly, unless and until superseded by anything done or any action taken under the enactment so extended.

6. For the purposes of facilitating the application in the transferred territories of the enactment specified in Schedule I or of any rule, regulation, notification, order, bye-law, direction or instruction referred to in section 3, any court or other authority may construe the same with such alterations, not affecting the substance, as may be necessary or proper to adopt it to the matter before the court or other authority.

Powers of courts and other authorities for purposes of facilitating the application of the enactment specified in Schedule I or rules, etc.

7. Nothing contained in this Act shall affect the power of the State Government or of any officer or authority, exercisable under the enactment specified in Schedule I, to add, amend, vary or rescind the rules, regulations, notifications, orders and bye-laws made, and directions or instructions issued, as extended by section 3 to the transferred territories.

Power to make rules, etc. not be affected.

8. If any difficulty arises in giving effect, in the transferred territories, to the provisions of the enactment specified in Schedule I, the State Government may, by order notified in the Official Gazette, make such provisions or give such directions as appear to it to be necessary or expedient for the removal of the difficulty.

Power to remove difficulties.

SCHEDULE-I
(See Section 3)

Serial No. 1	Year 2	Number of Act 3	Name of the Act 4
1.	1953	7	The Himachal Pradesh Compulsory Primary Education Act, 1953.

SCHEDULE-II
(See Section 6)

Serial No. 1	Year 2	Number of Act 3	Name of the Act 4
1.	1825	11	The Bengal Alluvion and Diluvion Regulation, 1825 as in force in the transferred territories.
2.	1920	1	The Punjab Limitation (Custom) Act, 1920, as in force in the transferred territories.
3.	1920	1	The Punjab Limitation (Custom) Act, 1920, as applied to the erstwhile princely State of Bilaspur.
4.	1931	2	The Punjab Municipal (Executive Officers) Act, 1931, as in force in the transferred territories.
5.	1938	9	The Punjab Debtor's Protection (Amendment) Act, 1938, as in force in the transferred territories.
6.	1941	5	The Punjab Jagirs Act, 1941, as in force in the transferred territories.
7.	1941	14	The East Punjab Electricity (Emergency Powers) Act, 1941, as in force in the transferred territories.
8.	1948	11	The East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, as in force in the transferred territories.
9.	1948	11	The East Punjab Molasses (Control) Act, 1948, as extended to the old areas by the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification No. F. 4/7/61-Jud.-II., dated the 16th June, 1962.
10.	1949	30	The East Punjab Drugs Control Act, 1948, as in force in the transferred territories.
11.	2008BK	1	The Pepsu Court of Wards Act, 2008 BK as in force in the areas which previously comprised in the erstwhile princely State of PEPSU and as now stands added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.
12.	1956	38	The Punjab Special Powers (Press) Act, 1956, as in force in the transferred territories.
13.	1957	18	The Punjab Court of Wards (Validation of Exercise of Powers) Act, 1957, as in force in the transferred territories.
14.	1960	39	The Punjab Primary Education Act, 1960, as in force in the transferred territories.
15.	1963	38	The Punjab State Faculty of Ayurvedic and Unani System of Medicines Act, 1963, as in force in the transferred territories.